Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Review Article

राजस्थान की राजनीति में विभिन्न जातीय समूहों की भूमिका: भीलवाड़ा जिले के विधानसभा चुनाव- 2018 के संदर्भ में आनुभविक अध्ययन

गणेश कुमावत *

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *गणेश कुमावत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18628719

सारांश

राजस्थान की राजनीति ऐतिहासिक रूप से जातीय संरचना से प्रभावित रही है, जहाँ विभिन्न जातीय समूह चुनावी व्यवहार, उम्मीदवार चयन और राजनीतिक दलों की रणनीतियों को निर्धारित करते हैं। भीलवाड़ा जिला, मेवाड़ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, जहाँ जाट, राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा व्यापारी वर्ग का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भीलवाड़ा जिले में जातीय समूहों की राजनीतिक भूमिका का आनुभविक विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में आसींद और मांडल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों, मतदान प्रतिशत, सामाजिक संरचना और दलों की चुनावी रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इस शोध के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि जातीय समीकरण अभी भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं, लेकिन विकास, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक कारक बन चुके हैं। यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक एवं आनुभविक पद्धति पर आधारित है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 02-01-2026
- **Accepted:** 23-01-2026
- **Published:** 13-02-2026
- **MRR:**4(2); 2026: 156-159
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

गणेश कुमावत. राजस्थान की राजनीति में विभिन्न जातीय समूहों की भूमिका: भीलवाड़ा जिले के विधानसभा चुनाव- 2018 के संदर्भ में आनुभविक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(2):156-159.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: जातीय राजनीति, राजस्थान चुनाव, भीलवाड़ा जिला, मतदान व्यवहार, सामाजिक संरचना।

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में जाति एक प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना है। विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में जातीय पहचान राजनीतिक सहभागिता और चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी जातीय समीकरणों का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया, हालांकि विकास और स्थानीय मुद्दों का महत्व भी बढ़ा है। भीलवाड़ा जिला राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सात विधानसभा क्षेत्र (आसींद, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़) हैं, जिनमें विभिन्न जातीय समूहों का प्रभाव अलग-अलग है।

© 2026 गणेश कुमावत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

भीलवाड़ा जिले का सामाजिक ताना-बाना अत्यंत विविधतापूर्ण है। गुर्जर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, मीणा और दलित समुदायों के साथ-साथ भील जैसी आदिवासी जनजातियाँ यहाँ की राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती रही हैं। प्रत्येक जातीय समूह न केवल अपनी संख्या-बल बल्कि संगठित मतदान की प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट हुई। इन चुनावों में विभिन्न जातीय समूहों ने अपने-अपने हितों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनावी निर्णय लिए है।

यह अध्ययन अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें आसींद और मांडल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की चुनावों में राजनीतिक भागीदारी, उनकी जातिगत पहचान, राजनीतिक झुकाव और चुनावी प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया गया है। इस शोध के आंकड़ों और सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि जातीय समूहों का प्रभाव केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों के चयन, दलों की रणनीति और चुनाव प्रचार की दिशा को भी निर्धारित करता है।

आसींद और मांडल विधानसभा क्षेत्र की राजनीति:

राजस्थान की राजनीति में जाति आधारित समीकरण सदैव निर्णायक कारक रहे हैं। आसींद और मांडल, दोनों ही भीलवाड़ा ज़िले की विधानसभा सीटें हैं, जिनकी भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि भिन्न होने पर भी इनमें कई समानताएँ मौजूद हैं। दोनों क्षेत्रों के 2018 के चुनावी परिप्रेक्ष्य को देखें तो जातिगत संरचना, मतदाता व्यवहार और दलों की रणनीतियों ने परिणामों को गहराई से प्रभावित किया। आसींद और मांडल दोनों सीटें सामान्य श्रेणी की है, हालांकि दोनों के चुनावी समीकरण में अलग-अलग जटिलताएँ सामने आती हैं। आसींद का क्षेत्र अपेक्षाकृत ग्रामीण और अनुसूचित जाति केंद्रित है। यहाँ मेघवाल, वाल्मीकि, जाटव जैसे दलित समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुर्जर, जाट और ओबीसी वर्ग संतुलनकारी शक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं। ब्राह्मण और राजपूत जैसे सामान्य वर्ग भले ही संख्या में कम हों, पर उनका आर्थिक-सामाजिक प्रभाव गहरा है।

इसके विपरीत, मांडल का सामाजिक ढाँचा अपेक्षाकृत संतुलित है। यहाँ अनुसूचित जाति (लगभग 15.88%) और अनुसूचित जनजाति (4.8%) के साथ जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, धाकड़, राजपूत और मुस्लिम समुदाय प्रभावी हैं। यह मिश्रण इसे त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की भूमि बनाता है। मांडल में 90% से अधिक जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर आधारित है, जो इसके चुनावी मुद्दों को भी आकार देती है।

स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में आसींद और मांडल दोनों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। आसींद में कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों और ग्रामीण गरीब वर्ग को अपने पक्ष में करके स्थायी आधार बनाया। लेकिन 1990 के दशक के बाद भाजपा का उदय हुआ और इसने दलित व ओबीसी मतदाताओं में पैठ बनाई। वर्तमान में आसींद में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता है, जिसमें मेघवाल समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है।

मांडल का इतिहास भी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। 1950–70 के दशक में कांग्रेस का दबदबा रहा, किंतु आपातकाल के बाद जेएनपी और 1990 के दशक से भाजपा मजबूत हुई। कालू लाल गुर्जर जैसे नेताओं ने भाजपा को क्षेत्र में स्थायी पहचान दिलाई। मांडल में मतदाता अक्सर सत्ता परिवर्तन करते रहे, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बना रहा।

जातीय समीकरण और मतदान व्यवहार

आसींद में जातीय पहचान चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अनुसूचित जातियों का बहुमत और ओबीसी का समर्थन किसी भी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कर सकता है। यहाँ गुर्जर और ब्राह्मण समुदाय की संख्या लगभग 55,000-55,000 है, जिनका झुकाव जिस दल की ओर होता है, जीत उसी के पक्ष में जाती है। कांग्रेस यहाँ परंपरागत रूप से दलित वोटों पर निर्भर रही है, जबकि भाजपा ने समावेशी हिंदुत्व और विकास आधारित राजनीति के सहारे अपनी पकड़ मजबूत की

मांडल में जातीय विविधता अधिक है। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, धाकड़ और मुस्लिम समुदाय वोटों के बंटवारे में निर्णायक हैं। यहाँ अनुसूचित जातियों के साथ-साथ जाट और ओबीसी भी बड़े पैमाने पर प्रभावी रहते हैं। मांडल में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव भी उल्लेखनीय है, जैसे 2018 में प्रद्युम्न सिंह और उदयलाल भड़ाना ने बड़ी संख्या में वोट हासिल किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ जातीय समीकरण के साथ-साथ व्यक्तिगत छवि भी उतनी ही निर्णायक है

आसींद में कांग्रेस परंपरागत रूप से सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीतियों पर जोर देती रही है, जबकि भाजपा विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखती है। यहाँ दल विशेष जातीय सम्मेलन और सामुदायिक नेताओं से संपर्क करके वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं।

मांडल में भाजपा और कांग्रेस के बीच बार-बार सत्ता परिवर्तन होता है। भाजपा यहाँ राष्ट्रीय लहर और स्थानीय नेतृत्व दोनों पर निर्भर रहती है, जबकि कांग्रेस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास पर जोर देती है। दिलचस्प पहलू यह है कि मांडल में निर्दलीय उम्मीदवार अक्सर चुनाव को त्रिकोणीय बना देते हैं, जिससे बड़े दलों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

दोनों सीटों के चुनावी आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण बताता है कि आसींद में 2008–2024 के चुनावी आँकड़े बताते हैं कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को यहाँ भारी समर्थन मिलता है (2019 में 73.4%), जबकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला होता है। कई बार तीसरे विकल्प (आरएलपी या स्वतंत्र) ने भी निर्णायक भूमिका निभाई है। मांडल में भी यही पैटर्न दिखता है। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, पर 2014 और 2019 में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। विधानसभा चुनावों में स्थिति अधिक उतार-चढ़ाव वाली रही—2008 में कांग्रेस, 2013 में भाजपा, 2018 में कांग्रेस और 2023 में फिर भाजपा विजयी रही। 2018 का चुनाव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा जब निर्दलीयों ने पारंपरिक दलों की स्थिति को चुनौती दी

समकालीन स्थिति देखें तो दोनों ही क्षेत्रों में हाल के वर्षों में युवा मतदाता जातिगत पहचान के साथ-साथ विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय एकजुटता अभी भी निर्णायक है, पर शहरी और कस्बाई मतदाता धीरे-धीरे मुद्दा-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। यह

© 2026 गणेश कुमावत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिवर्तन संकेत करता है कि आने वाले समय में जाति के साथ-साथ विकास आधारित विमर्श भी मजबूत होगा

आसींद और मांडल दोनों ही सीटें राजस्थान की राजनीति में जातीय समीकरणों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। जहाँ आसींद अनुसूचित जाति केंद्रित राजनीति का उदाहरण है, वहीं मांडल जातीय विविधता और बार-बार सत्ता परिवर्तन की विशेषता रखता है। दोनों क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहता है, परंतु तीसरे विकल्प समय-समय पर निर्णायक साबित होते हैं। जाति अभी भी प्रमुख कारक है, लेकिन धीरे-धीरे विकास आधारित राजनीति भी अपनी जगह बना रही है। इस तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की राजनीति में जाति और विकास दोनों की जटिल अंतःक्रिया भविष्य की दिशा तय करेगी।

आसींद एवं मांडल विधानसभा चुनाव-2018: तुलनात्मक विश्लेषण

राजस्थान की राजनीति में जातिगत संरचना और सामाजिक आधार लंबे समय से निर्णायक कारक रहे हैं। भीलवाड़ा जिले की दो प्रमुख सीटें—आसींद (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) और मांडल (सामान्य)—2018 के चुनावों में जाति और सामाजिक कारकों के विविध स्वरूपों को दर्शाती हैं। प्रस्तुत तुलनात्मक विश्लेषण दोनों क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे, शैक्षणिक स्थिति, आय-वितरण, मतदाता जागरूकता, राजनीतिक झुकाव और जातिगत समीकरणों के आधार पर किया गया है। दोनों ही क्षेत्रों में जाति, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक रुझानों का गहन प्रभाव देखा गया, किंतु इनके स्वरूप और परिणाम भिन्न रहे हैं।

आसींद और मांडल दोनों ही मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र हैं। आसींद अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है, जहाँ मेघवाल, वाल्मीकि और जाटव जैसी जातियों का गहरा प्रभाव है। मांडल अपेक्षाकृत मिश्रित जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ अनुसूचित जाति, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय प्रभावी हैं। दोनों क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक संरचना लगभग एक जैसी है।

दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण में कुल 200–200 उत्तरदाता शामिल किए गए। आसींद में पुरुष और महिला का अनुपात बराबर रहा, जबकि मांडल में महिलाओं की भागीदारी (52%) पुरुषों (48%) से अधिक थी। आयु वर्ग के आधार पर दोनों क्षेत्रों में मध्यम आयु (41–60 वर्ष) के मतदाता सबसे अधिक पाए गए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक सक्रियता का केंद्र वर्ग मध्य आयु वर्ग है, और यह वर्ग ही चुनावी राजनीति का दिशा-निर्धारण करता है।

शैक्षणिक स्थिति की तुलना करने पर पाया गया कि दोनों ही क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा संतोषजनक है, लेकिन स्नातक और उससे अधिक स्तर पर स्थिति कमजोर है। विशेषकर महिलाओं में उच्च शिक्षा का प्रतिशत कम है। आसींद और मांडल दोनों ही जगह पुरुषों की तुलना में महिलाएँ स्नातक स्तर पर पिछड़ी हुई दिखाई देती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में लैंगिक असमानता अभी भी विद्यमान है, जो दीर्घकालिक रूप से राजनीतिक चेतना और भागीदारी को प्रभावित करती है।

व्यवसायिक संरचना की दृष्टि से दोनों क्षेत्रों में कृषि ही प्रमुख आधार है। आसींद में 59% और मांडल में 61% उत्तरदाता कृषि से जुड़े पाए गए। व्यवसाय से जुड़े लोगों का प्रतिशत क्रमशः 23% और 21% रहा। नौकरीपेशा और श्रमिक वर्ग की संख्या दोनों ही क्षेत्रों में 10% से भी कम रही। इससे स्पष्ट होता है कि आसींद और मांडल दोनों ही रोजगार विविधीकरण से वंचित हैं और आज भी कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं।

दोनों क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। आसींद में 66% और मांडल में 63.5% परिवारों की मासिक आय पाँच हजार रुपये से कम पाई गई। 20,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले परिवारों का अनुपात क्रमशः 9% और 7% रहा। यह स्थिति दर्शाती है कि अधिकांश परिवार निम्न आय वर्ग में आते हैं और गरीबी यहाँ एक स्थायी समस्या के रूप में मौजूद है।

लोकतांत्रिक चेतना का स्तर दोनों क्षेत्रों में उच्च स्तर पर है। आसींद में 89.5% और मांडल में 85% उत्तरदाताओं ने 2018 के चुनाव में मतदान किया है। रोचक तथ्य यह है कि दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं में राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने की प्रवृत्ति सशक्त हो रही है।

आसींद में भाजपा को कांग्रेस की तुलना में अधिक समर्थन मिला है। यहाँ भाजपा को 40.5%, कांग्रेस को 34% और आरएलपी व अन्य को 21.5% मत प्राप्त हुए। वहीं मांडल में कांग्रेस (42.5%) भाजपा (33.5%) से आगे रही और शेष मत स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिले। इससे स्पष्ट है कि आसींद में भाजपा का प्रभाव अपेक्षाकृत मजबूत रहा, जबकि मांडल में कांग्रेस को बढ़त मिली।

दोनों क्षेत्रों में प्रत्याशी की छवि और विकास कार्य प्रमुख कारक रहे। आसींद में प्रत्याशी की छवि को 32.5% और विकास कार्यों को 29% उत्तरदाताओं ने प्राथमिकता दी। मांडल में भी यही रुझान देखा गया, जहाँ 38% ने प्रत्याशी की छवि और 29.5% ने विकास कार्य को अहम माना। जातिगत समीकरण आसींद में 18% और मांडल में 14% मतदाताओं के लिए महत्त्वपूर्ण रहे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति का प्रभाव अभी भी मौजूद है, किंतु मतदाता अब विकास और नेतृत्व की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगे हैं।

आसींद में 32% और मांडल में 34.5% उत्तरदाताओं ने माना कि चुनाव प्रचार में जातिगत अपील की गई। हालांकि दोनों ही क्षेत्रों में अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसे नकारा। यह दर्शाता है कि जातिगत राजनीति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, परंतु उसका प्रभाव घटता हुआ प्रतीत होता है।

आसींद में विकास मुद्दे (29%) और प्रत्याशी की छवि (27.5%) निर्णायक रहे। जातिगत समीकरण तीसरे स्थान (26.5%) पर रहे। मांडल में भी यही रुझान दिखा—विकास और प्रत्याशी की छवि शीर्ष पर, जबकि जातिगत समीकरण अपेक्षाकृत कमजोर साबित हुए। दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव में मतदाता अब जातिवाद की राजनीति से हटकर विकास और नेतृत्व की गुणवत्ता की ओर झुक नजर आ रहे हैं।

आसींद और मांडल के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही क्षेत्र कृषि प्रधान, निम्न आय वाले और शैक्षिक दृष्टि से आंशिक रूप से पिछड़े हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उल्लेखनीय है और पुरुषों से अधिक सक्रिय दिखाई देती है। आसींद में भाजपा की स्थिति मजबूत रही, जबकि मांडल में कांग्रेस को बढ़त मिली। दोनों ही क्षेत्रों में

© 2026 गणेश कुमावत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

जातिगत प्रभाव बना हुआ है, लेकिन यह निर्णायक कारक नहीं रहा है। अब मतदाता विकास कार्यों और प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति राजस्थान की राजनीति में जाति आधारित राजनीति से विकास-उन्मुख लोकतांत्रिक परिपक्वता की ओर संक्रमण को दर्शाती है।

निष्कर्ष

इस शोध के आंकड़ों और सर्वेक्षणों से प्राप्त निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि जातीय समूहों का प्रभाव केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों के चयन, दलों की रणनीति और चुनाव प्रचार की दिशा को भी निर्धारित करता है। आसींद और मांडल विधानसभा क्षेत्र का आनुभविक अध्ययन यह संकेत देता है कि राजस्थान की राजनीति में जातिगत राजनीति का प्रभाव कम होते हुए विकास-आधारित और नेतृत्व-आधारित राजनीति की ओर संक्रमण हो रहा है और अब जनता विकास, रोजगार, शिक्षा और ईमानदार नेतृत्व को अपने मतदान व्यवहार में प्रमुख आधार मानने लगी है। लोकतांत्रिक परिपक्वता का यह संकेत भविष्य की राजनीति की दिशा को निर्धारित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. Mathur TK. Feudal Polity in Mewar, 1750–1850 A.D. Jaipur: Publication Scheme; 1987.
2. इन्दा उ. राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष: राज्य शासन एवं राजनीति. जोधपुर: राजस्थानी ग्रंथागार; 2005.
3. राजपुरोहित केएल. स्वाधीनता संग्राम में राजस्थान की आहुतियाँ (1805 ई.–1947 ई.). दिल्ली: साइंटिफिक पब्लिशर्स; 2020.
4. Government of Rajasthan. Bhilwara District Gazetteer. Rajasthan; 1962 (reprint).
5. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. District Census Handbook: Bhilwara (Part XII B). Census of India 2011.
6. India State Assembly. Bhilwara Assembly Fact Book.
7. Huja R. A History of Rajasthan. Delhi: Rupa & Company; 2009.
8. चूण्डावत ल. बडग़ावत देवनारायण महागाथा. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 1960.
9. चतुर्वेदी स. नाहर नृत्य. नवभारत टाइम्स. 2023 Mar 20.
10. जोशी न. मांडल नाहर नृत्य उत्सव. एनडीटीवी राजस्थान. 2024 Apr 07.
11. Government of Rajasthan. Rajasthan District Gazetteer: Bhilwara. 1975.
12. Government of Rajasthan, Town Planning Department. Asind Master Plan (2010–2031). Rajasthan; 2010.
13. Election Commission of Rajasthan. Election data and reports. Rajasthan Government.
14. शोध सर्वे द्वारा एकत्रित आंकड़े.
15. Census of India. Primary census abstract, population by districts and sub-districts: Bhilwara district (Rajasthan). New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India; 2011.
16. Kumar A. Caste and politics in Rajasthan: A case study of Bhilwara district. Indian J Polit Sci. 2013;74(2):285–300.
17. Chandra K. Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Count in India. New York: Cambridge University Press; 2004. p. 51–52.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

गणेश कुमावत राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग से "राजस्थान की राजनीति में विभिन्न जातीय समूहों की भूमिका: भीलवाड़ा जिले के विधानसभा चुनाव- 2018 के संदर्भ में आनुभविक अध्ययन" विषय पर पी.एचडी. कर रहे हैं।

© 2026 गणेश कुमावत. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/